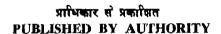


अज्ञाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—इण्ड 3—उप-इण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)





₩. 446}

मई विल्ली, मंगलबार, अगस्त 7, 1990/भावण 16, 1912

No. 446]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 1990/SRAVANA 16, 1912

इ.स. भागमें भिल्ल पृष्ट संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रचा वा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

लाद्य और नागरिक पृति मंत्रास्य

(नागरिक पूर्ति विभाग)

श्रादेश

नई दिल्ली, 7 प्रगस्त, 1990

का. श्रा. 624(अ): --केन्द्रीय सरकार, श्रावण्यक वस्तु ग्राधिनयम, 1955 (1955 का 10) की घारा 5 द्वारा प्रशस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व उद्योग भीर नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति ग्रीर सहकारिता विभाग) द्वारा जारी किए गए. श्रादेश सं.का. श्रा. 681 (अ) तारीख 30 नवस्वर, 1974 का संशोधन करने का निस्नलिखित श्रादेश जारी करती हैं:—

- (i) भावषयक वस्तु अर्थिनियम. 1955 की धारा 3 की उपधारा (2) के खरू (धा क अर्धान मिनिया का प्रयाजन अर्हातक उनका संबंध अनुकाष्ति वा परिमट द्वारा फ्टकर संबंध वितरण के विनियमन से है विखंडित किया जाता है, जो तुरन्त प्रभाषी होगा:
- (ji) वं सभी प्रादेश (जिन्हे इसमें इसक पश्चात् उक्त प्रादेश कहा गक्षा है) जो किसी राज्य सरमः:र या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने पूर्वोक्त स्रादेश द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने हुए जारी किए है, उपर (i) में विनिधिष्ट सीमा तक उपतिरित्त किए जाने हैं।

परन्तु यह कि उक्त उपारण -

(क) उक्त आदोश का पूर्वतन प्रवर्तन या उसके अधीन सम्प्रक् रूप से की गई या होने की गई कोई बात ; या

- (स्त्र) उक्त भादेण के अर्धान अजित, प्रौदन्त या उपगत कोई अधिकार,
 विशेषाधिकार, बाध्यता या दावित्व; या
- (ग) उक्त प्रायेश के विख्य किए गए किसी ग्रगरात्र की बाबत उपगत कोई शास्ति या दंद; या
- (घ) पूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार विजेपाधिकार, बाध्यता, दायित्व, गास्ति या दंड के वावत कोई प्रस्थेषण, विधिक्त कार्यवाही या उपचार, को प्रभावित नहीं करेगा।

भीर ऐसा कोई ग्रन्थेयग, विधिक कार्यशही या उपचार संस्थित की जा सकेंगी. चालू रखी जा सकेंगी या प्रक्तिनशाल की जा लंकेगी भीर ऐसी कोई शास्ति या दंड प्रारोपित किया जा सकेंगा जैसे कि उक्ष्त आदेल का उपान्तरण स किया गया हो।

[फा॰ स॰ 26(3)/90-ई मी श्रार एण्ड हें] बो. एन. बहादुर, संयुक्त सजिब

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

ORDER

New Delhi, the 7th August, 1990

S.O. 624(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government makes the following Order to amend Order No. S.O. 681(E) dated the 30th November, 1974 issued by the erstwhile Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Cooperation), as follows:—

- (i) that the delegation of powers under clause (d) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 in so far as it relates to the regulation of retail cement distribution by licences or permits shall stand rescinded with immediate effect;
- (ii) that all orders (hereinafter referred to as the said orders) issued by a State Government or a Union Territory Administration in exercise of the powers delegated to them by the aforesaid Order shall stand modified to the extent specified in (i) above.

Provided that such modification shall not allect-

- (a) the previous operation of the said Order or anything duly done or suffered thereunder; or
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Order; or
- (c) any penalty or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Order; or
- (d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty or punishment as aforesaid,

And any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty or punishment may be imposed as if the said Order had not been modified.

[F.No. 26(3)/90-ECR&E] B.N. BAHADUR, Jt. Secy.